भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2101
उत्तर देने की तारीख 9 दिसंबर, 2024
सोमवार, 18 अग्रहायण 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण

2101. श्री इमरान मसूदः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के चार चरणों में से किसी के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश, विशेषकर सहारनपुर जिले में रोजगार पाने वाले या अपना स्वयं का रोजगार इकाई स्थापित करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आईटीआई के पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यशालाएं आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इस स्कीम के पहले तीन चरणों अर्थात पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जिन्हें वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया था। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, जो वर्तमान में वित्त-वर्ष 2022-23 से कार्यान्वयन के अध्यधीन है, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और वे इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इस स्कीम के पहले तीन चरणों में कुल 3,81,423 लाख उम्मीदवारों को या तो रोजगार मिल या वे स्व-रोजगार में लगे। इनमें से 8,107 उम्मीदवार सहारनपुर से थे।

(ख) और (ग) पीएमकेवीवाई 4.0 को उद्योग और बाजार की क्षेत्रीय मांग के अनुसार उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करने के लिए मांग-संचालित स्कीम के रूप में तैयार किया गया है। इसके अलावा, यह स्कीम आधुनिक युग और उभरते पाठ्यक्रमों जैसे ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग (आईओटी), 3डी प्रिंटिंग, ब्लॉक चेन, मेक्ट्रोनिक्स और रोबोटिक्स आदि पर भी ध्यान केंद्रित करती है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, कृत्रिम मेधा (एआई) से संबंधित जॉब रोलों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	जॉब रोलों के नाम	प्रशिक्षित/उन्मुख
i.	एआई - बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट	883
ii.	एआई - डेटा आर्किटेक्ट	475
iii.	एआई - डेटा इंजीनियर	708
iv.	एआई - डेटा क्वालिटी एनालिस्ट	3,642
v.	एआई - डेटा साइंटिस्ट	1,796
vi.	एआई - मशीन लर्निंग इंजीनियर	2,135
vii.	एआई - सॉल्यूशन आर्किटेक्ट	241
viii.	एआई और एमएल - जूनियर टेलीकॉम डेटा एनालिस्ट	164
ix	एआई डिवाइस इंस्टॉलेशन ऑपरेटर	165
योग		**10,209**

इसके अलावा, एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म आरंभ किया है, जो कौशलोन्न्यन हेतु एक व्यापक और सुलभ प्लेटफॉर्म है, जो देश के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल पाठ्यक्रम, रोजगार के अवसर और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है। एसआईडीएच उम्मीदवारों के कौशल आकलन को बढ़ाने और प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की सिफारिश करने के लिए उन्नत एआई और मशीन लर्निंग तकनीकों का लाभ उठाता है। यह एआई/एमएल-संचालित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्लेटफॉर्म अनुरूप कौशल मूल्यांकन और व्यक्तिगत शिक्षण मार्ग प्रदान करता है, जिससे उम्मीदवारों को अपनी अर्हता बढ़ाने और संगठनों को शीर्ष प्रतिभाओं की पहचान करने में सहायता मिलती है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने वर्ष 2024 में शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट' पर एक वर्षीय एनएसक्यूएफ़ 3.5 स्तरीय संरेखित पाठ्यक्रम शुरू किया है, ताकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के माध्यम से एआई आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सभी सीटीएस शिक्षुओं के लिए 7.5 घंटे का माइक्रो-क्रेडेंशियल कोर्स, "कृत्रिम मेधा (एआई) का परिचय विकसित किया गया है।

(घ) और (ङ) पीएमकेवीवाई 4.0 को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं। यह स्कीम मांग आधारित है और उद्योग तथा बाजार में कुशल कार्यबल की क्षेत्रीय मांग को पूरा करती है। इस योजना में विशेष परियोजनाओं का प्रावधान है, जिनका लक्ष्य कम प्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों- एससी/एसटी/महिला/दिव्यांगों और आकांक्षीय जिलों, वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, जनजातीय जिलों आदि जैसे भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करना है। कौशल विकास कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, जनजातीय समुदायों और अन्य सीमांत समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्तमान में, देश में 11,243 ग्रामीण आईटीआई स्थापित हैं, जिनमें से 2,396 आईटीआई सरकारी आईटीआई हैं और 8847 निजी आईटीआई हैं।

*****